Hindustan Times | Chandigarh | October 28, 2017

Housing for all needs to go beyond numbers, say experts

HT Correspondent
chandigarh@hindustantimes.com

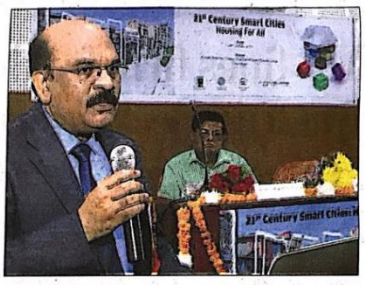

CHANDIGARH: The formal sector, including government and the private, alone will not be able to meet the targets of housing for all, and the participation of the stakeholders, including the poor, will be needed, this was one of the suggestions at a seminar on '21st Century Smart Cities - Housing for All' held here on Saturday.

Punjab regional chapter (PRC), institute of town planner, India (ITPI), in collaboration with centre for science and environment (CSE) organised the seminar.

The dire need is to incorporate the requirements for the impoverished population in the formal housing provisions, considering the lower income rung constitutes 96% of the national housing shortage.

The big question today is not how to provide for affordable housing for urban poor, instead, it is how to build them in a way that is comfortable, resource efficient, sustainable and most importantly affordable for all," said Anumita Roychowdhury, executive director, CSE.

The importance of technological innovation and synergy of action between state and central governments was emphasised by PSN Rao, chairman, Delhi urban arts commission.

He also laid stress on the need for states to gear up for formulation of comprehensive housing policies with a strong focus on inclusion of the weaker sections of the society.

Experts highlighted importance of technological innovation and synergy of action between state and central governments. HT PHOTO

ISSUES RELATED TO POLICIES, CONTRIBUTION OF PRIVATE PLAYERS AND PEOPLE IN MAKING SUSTAINABLE, AFFORDABLE AND EFFICIENT PROJECTS DISCUSSED

Gurpreet Singh, PRC chairman, ITPI, said, "Punjab government has initiated steps and policies to provide housing to the disadvantageous groups of the society.

Sharing his experience from Maharashtra, KS Akode, president ITPI and chief planner, Maharashtra Industrial Development Corporation (MIDC) stressed on the complex issue of slums on green zones.

He informed that the state of Maharashtra is preparing a proposal for Unified Building byelaws in which municipalities (category A, B and C) shall have appropriate address to the prevalent issues.

Dr DS Meshram, president emeritus, ITPI summarised the raised concerns by key speakers over the provision of housing for the weaker sections of the society and said that "it is our (planners') duty to mandate how our schemes and policies capture the requisites in a sustainable manner."

Urban scholars bring forth issue of affordable housing

TIMES NEWS NETWORK

Mohali: Punjab Regional Chapter (PRC) of Institute of Town Planner, India (ITPI), in collaboration with Centre for Science and Environment, India (CSE) organised a one-day north zone seminar on "21st century smart cities—Housing for all"—at Punjab Regional Chapter Building in Chandigarh on Saturday.

More than 100 participants including town planners and architects from Punjab, Haryana and Himachal Pradesh along with students of various school of planning of the region participated in this seminar.

The main aim of the event was to gather information and explore solutions to facilitate quality habitat for the rapidly rising urban population in India. Gurpreet Singh, chairman of PRC, ITPI welcomed urban planners, architects, researchers, government personnel and academicians who were present at the venue.

"The main hurdle is not to provide affordable housing for urban poor. Instead the focus should be on comfortable, resource efficient, sustainable and affordable housing," said Anumita Roy Chowdhury, executive director of CSE.

She highlighted the dire need to incorporate the basic amenities of the impoverished population in the formal housing provisions considering the fact that lower strata constitutes 96% of the national housing shortage.

PSN Rao, chairman of Delhi Urban Arts Commission apprised the attendees about various national policies like RAY, PMAY (Pradhan Mantri Awas Yaojana) and the need to formulate comprehensive housing policies with a strong impetus on inclusion of weaker sections of society.

The chief guest, KS Akode, president of ITPI and chief planner of MIDC (Maharashtra Industrial Development Corporation) shared his experiences of Maharashtra and stressed on the complex issue of slums around green zones. He informed that the state is preparing a proposal for 'Unified Building Bylaws' in which municipalities (category A, B and C) shall have appropriate address to the prevailing issues.

Dainik Savera Times/Chandigarh | October 28, 2017

'भारत में सस्ती हाऊसिंग' के विवादास्पद विषय पर एकदिवसीय संगोष्ठी

चंडीगढ़, 28 अक्तूबर (नरेश): पंजाब क्षेत्रीय अध्याय (पी.आर.सी.), इंस्टीच्यूट ऑफ टाऊन प्लानर, इंडिया (आई.टी.पी.आई.) ने सैंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमैंट, भारत (सी.एस.ई.) के सहयोग से पंजाब क्षेत्रीय अध्याय में '21वीं शताब्दी स्मार्ट शहरें-सभी के लिए आवास' पर एक दिवसीय उत्तर क्षेत्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया। आज 35-बी चंडीगढ़ की टाऊन प्लानिंग बिल्डिंग में भारत में तेजी से बढ़ते शहरी निवासियों के लिए गुणवत्ता वाले आवास की सुविधा के लिए अंतर्दृष्टि एकत्र करना और समाधान तलाशना था। कार्यक्रम में देश के उत्तरी और पश्चिमी हिस्सों से शहरी नियोजक, आर्किटैक्ट्स, शोधकर्त्ताओं, सरकारी कर्मियों और शिक्षाविदों का स्वागत पी.आर.सी. के अध्यक्ष गुरप्रीत सिंह ने किया।

सी.एस.ई. कार्यकारी निदेशक अनुपमिता राय चौधरी ने कहा कि आज बड़ा सवाल यह नहीं है कि शहरी गरीबों को किफायती आवास कैसे प्रदान करना है, इसके बजाय यह उन तरीकों से तैयार करना है जो सहज, संसाधन कुशल, टिकाऊ और सबसे महत्वपूर्ण रूप से सस्ती हैं। राय चौधरी ने इस तथ्य के प्रति सचेत होने की जरूरत को रखकर चर्चा की और मंजिल को निर्धारित किया कि भारत का 60 प्रतिशत अभी तक बनाया जाना बाकी है। इसका मतलब है कि प्राकृतिक संसाधनों की व्यापक खपत होगी। उन्होंने औपचारिक आवास प्रावधानों में गरीब आबादी की आवश्यकताओं को शामिल करने के लिए सख्त जरूरत पर प्रकाश डाला जिससे कम आय वाले हिस्से में राष्ट्रीय आवास की कमी का 96 प्रतिशत हिस्सा बना।

भारत में सस्ती हाऊसिंग के विवादास्पद मुद्दे पर चर्चा करती हुई सी.एस.ई. की कार्यकारी निदेशक अनुपमिता राय चौधरी व दिल्ली शहरी आर्ट्स कमिशन के अध्यक्ष पी.एस.एन. राव व हिस्सा लेते प्रतिभागी। (जगमोहन)

दिल्ली शहरी आर्ट्स कमिशन के अध्यक्ष पी.एस.एन. राव ने विभिन्न राष्ट्रीय आवास नीतियों यानी आर.ए.ई., पी.एम.ए.ई. (प्रधान मंत्री आवास योजना) और राज्यों की व्यापक आवास नीतियों को तैयार करने की आवश्यकता पर एक अंतर्दृष्टि प्रदान करके चर्चा को आगे बढ़ाया। समाज के कमजोर वर्गों को शामिल करने पर एक मजबूत फोकस के साथ मुख्यातिथि के.एस. अठोड़, अध्यक्ष आई.टी.पी.आई. और मुख्य नियोजक एम.आई.डी.सी. (महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम) ने महाराष्ट्र राज्य से अनुभव साझा किए और ग्रीन जोन पर मलिन बस्तियों के जटिल मुद्दे पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र राज्य एकीकृत बिल्डिंग बायलॉज के लिए एक प्रस्ताव तैयार कर रहा है जिसमें नगर पालिका (श्रेणी ए, बी और सी) के पास प्रचलित मुद्दों के लिए उचित पता होगा।

एस.डी. सैनी, उपाध्यक्ष आई.टी.पी.आई. और पूर्व चीफ प्लानर हरियाणा और डा. नजामुद्दीन, महासचिव आई.टी.पी.आई. और प्रोफैसर एमेरेट्स आई.आई.टी. रुड़की ने नीतियों की शोध और मजबूत बनाने की जरूरत जताई जो कि एक स्थायी आवास प्रदान करने की राष्ट्रीय समस्याओं का सामना करते हैं।

डा. डी.एस.एस. श्राम अध्यक्ष एमेरेट्स, आई.टी.पी.आई. ने समाज के कमजोर वर्गों के लिए आवास के प्रावधान के बारे में प्रमुख वक्ताओं द्वारा उठाई गई चिंताओं को संक्षेप में प्रस्तुत किया और कहा कि हमारी योजनाओं और नीतियों में यह आवश्यक है कि हमारी योजनाएं और नीतियां टिकाऊ ढंग से है।

टाऊन प्लानर्स के बीच 100 से अधिक प्रतिभागियों, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के आर्किटैक्ट्स ने इस सैमीनार में भाग लिया।

chandigarh.amarujala.com October 28, 2017

हाउसिंग फॉर आल को लेकर हुआ मंथन

मोहाली। सेक्टर-35 स्थित पंजाब रीजनल चैप्टर (पीआरसी), इंस्टीट्यूट ऑफ टाऊन प्लानर व सेंटर फॉर साइंस एंड एन्वायनमेंट के सहयोग से एक सेमिनार करवाया गया। इसमें 21वीं शताब्दी में स्मार्ट सिटीज-हाउसिंग फार ऑल नाम दिया गया। सेमिनार का उद्देश्य तेजी से बढ़ रहे शहरी एरिया के लोगों गुणवत्ता वाले आवास की सुविधा देना था। इस दौरान पीआरसी के चेयरमैन गुरप्रीत सिंह ने सेशन का आगाज किया। उन्होंने विस्तार से अपने विचार रखे। इसी तरह सीएसई की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनुमिता राय चौधरी ने कहा कि शनिवार को बड़ा सवाल यह नहीं है कि शरीरी गरीबों के लिए किफायती आवास कैसे प्रदान किए जाए। बल्कि सस्ते आवास बढिया तरीके से सहज, संसाधन, कुशल को कैसे तैयार करे। इसके अलावा कई अन्य वक्ताओं ने भी अपने विचार रखे। इस मौके पर दिल्ली अर्बन आर्ट्स कमीशन दिल्ली के पीएस राओ, प्रेसिडेंट आईटीपीआई केएस अकोड़े, वोइस प्रेसिडेंट एसडी सैनी समेत कई माहिरों ने अपनी बात रखी। वहीं, समागम में सौ करीब टाऊन प्लान, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल के आर्किटेक्ट व स्टूडेंट ने हिस्सा लिया।